www.rojgarsamachar.gov.in
www.employmentnews.gov.in

सत्यमेव जयते

अंग्रेजी एवं उर्दू में भी प्रकाशित
वार्षिक शुल्क : ₹ 530

रोज़गार समाचार

साप्ताहिक

खंड 44 अंक 42 पृष्ठ 56 | नई दिल्ली 18 - 24 जनवरी 2020 | ₹ 12.00

मानव संसाधन विकास में पहल और उपलब्धियां

वर्ष 2019 में डॉ. के. कस्तूरीरंगन समिति ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' को राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप सौंपा. भारत सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान के संबंध में लोगों की गतिशील जरूरतें पूरी करने के लिए नई शिक्षा नीति तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की थी, जिसका लक्ष्य भारत को ज्ञान के क्षेत्र में सुपर पावर बनाना है. इसके लिए देश के विद्यार्थियों को आवश्यक कौशल और ज्ञान से युक्त बनाना और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शैक्षिक और उद्योग क्षेत्र में कार्मिकों की कमी पूरी करना आवश्यक है.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पहल-निष्ठा शुरू किया ताकि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के परिणामों में समग्र सुधार लाया जा सके. इसके लिए एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षक कार्यक्रम और प्रधानमंत्री नवीन शिक्षण कार्यक्रम (ध्रुव) शुरू किए गए. इन कार्यक्रमों के जरिए प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान करने और उनके कौशल और ज्ञान को समृद्ध बनाने पर बल दिया जाता है. इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने उच्चतर शिक्षा विभाग में भी कई नए कार्यक्रम शुरू किए ताकि देश में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके. मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग ने पांच वर्ष की अवधि के लिए एक लक्ष्य योजना को भी अंतिम रूप दिया और इसे शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन और समावेशन कार्यक्रम (इक्विप-एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इन्क्लूजन प्रोग्राम) नाम से प्रकाशित किया. 2019 के अन्य प्रमुख कार्यक्रमों में स्वयं 2.0, दीक्षारंभ और परामर्श शामिल हैं.

निष्ठा - स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र प्रगति के लिए राष्ट्रीय पहल

प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के परिणामों में सुधार लाने के राष्ट्रीय प्रयास के रूप में एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा - (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र प्रगति के लिए राष्ट्रीय पहल) का शुभारंभ 21 अगस्त 2019 को किया गया. इस एकीकृत कार्यक्रम का लक्ष्य करीब 42 लाख शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों (एससीईआरटीज़) और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डीआईईटीज़) के संकाय सदस्यों, खंड संसाधन समन्वयकों और क्लस्टर संसाधन समन्वयकों की क्षमता का निर्माण करना है. यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सरकार के 100 दिन के कार्यक्रम के लिए दो रूपांतरकारी विचारों में से एक के रूप में शामिल किया गया है. यह अपनी तरह का पहला प्रयास है, जिसमें मानक प्रशिक्षण मॉड्यूल सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किए जा रहे हैं. परंतु, निष्ठा के बुनियादी विषयों और प्रत्याशित परिणामों को ध्यान में रखते हुए राज्य और संघ शासित प्रदेश भी प्रशिक्षण मॉड्यूल की परिकल्पना कर सकते हैं और स्वयं की सामग्री और ज्ञानवान व्यक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं.

ध्रुव - प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम

ध्रुव का लक्ष्य एक ऐसे मंच के रूप में काम करना है, जो विशिष्ट और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की प्रतिभा की खोज करने और उन्हें अपनी अपनी रुचि के विशिष्ट क्षेत्रों में चाहे वे विज्ञान, मंच कलाएं, मौलिक लेखन आदि, जो भी हों, में उत्कृष्टता हासिल करने में मदद करना है. इन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से यह उम्मीद की जाएगी कि वे अपनी क्षमता का पूर्ण इस्तेमाल करने के अलावा समाज में भी बड़ा योगदान करें. ध्रुव कार्यक्रम में देश के सभी भागों के बच्चों को शामिल किया जाता है, जिससे 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की सही भावना व्यक्त होती है.

स्कूली शिक्षा के लिए एकीकृत ऑनलाइन जंक्शन 'शगुन'

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने 28 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में विश्व के एक सबसे बड़े कार्यक्रम 'स्कूली शिक्षा के लिए एकीकृत ऑनलाइन जंक्शन 'शगुन' का शुभारंभ

किया. शगुन (URL: http://shagun.govt.in/) स्कूल शिक्षा प्रणाली में सुधार का अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें भारत सरकार और सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की विभिन्न गतिविधियों से संबंधित सभी ऑनलाइन पोर्टलों और वेबसाइटों के लिए एक जंक्शन का निर्माण किया गया है. शगुन के अंतर्गत अन्य संगठनों के अलावा 1200 केंद्रीय विद्यालयों, 600 नवोदय विद्यालयों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध 18000 अन्य स्कूलों, 30 एससीईआरटीज़, एनटीसीई से सम्बद्ध 19000 संगठनों को जोड़ा गया है. नव निर्मित जंक्शन पर देशभर के 15 लाख से अधिक स्कूलों के रिपोर्ट कार्ड उपलब्ध हैं. यह पोर्टल लगभग 92 लाख शिक्षकों और 26 करोड़ विद्यार्थियों को जोड़ता है. वेबसाइट एक सुदृढ़ फीडबैक व्यवस्था प्रदान करती है. सामान्य जन स्कूलों के बारे में सीधे अपनी फीडबैक उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे जन भागीदारी में और इजाफा होगा और उत्तरदायित्व तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी.

शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने का प्रयोजन देश में कुछ उत्कृष्टतम शिक्षकों के बेजोड़ योगदान को मान्यता प्रदान करना और उन शिक्षकों को सम्मानित करना है, जो अपनी प्रतिबद्धता और श्रम से न केवल स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाते हैं, बल्कि अपने विद्यार्थियों के जीवन को भी समृद्ध बनाते हैं. 2019 में जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर, तीन स्तरीय चयन प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन स्वयं नामांकन प्रक्रिया अपनाई गई. स्वतंत्र राष्ट्रीय ज्युरी ने 46 शिक्षकों के नाम अनुशंसित किए. राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में रजत पदक, प्रमाणपत्र और 50,000 रुपये नकद दिए जाते हैं.

परीक्षा पे चर्चा - 2.0

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 29 जनवरी, 2019 को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा 2.0 के हिस्से के रूप में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से वार्तालाप किया. 90 मिनट तक चले इस वार्तालाप में विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों ने हास्य विनोद पूर्ण वातावरण में सकून महसूस किया और प्रधानमंत्री के विचारों का बार बार स्वागत किया. देशभर से विद्यार्थियों और विदेश में रह रहे भारतीय विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया.

सोशल मीडिया सम्पर्क और संचार के बारे में राष्ट्रीय कार्यशाला

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिसंबर माह में ''सोशल मीडिया संपर्क और संचारः प्रबंधन एवं उत्कृष्ट पद्धतियों के बारे में राष्ट्रीय कार्यशाला'' आयोजित की. केंद्र द्वारा वित्त पोषित विभिन्न शैक्षिक संस्थानों से करीब 200 सोशल मीडिया विशेषज्ञों ने कार्यशाला में हिस्सा लिया. इस कार्यशाला का लक्ष्य विभिन्न संस्थानों के सोशल मीडिया संचार और सम्पर्क को एक संस्था के नीचे लाना और एक ऐसा चैनल खोलना था, जिस पर इन संस्थानों के साथ रोज़मर्रा संचार और संवाद स्थापित किया जा सके.

शिक्षा प्लस के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडीआईएसई+)

देश में सभी स्कूलों से गुणवत्तापूर्ण, भरोसेमंद और समय पर जानकारी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा पुनर्गठित प्रणाली यूडीआईएसई+ प्रारंभ की गई. जीआईएस आधारित मैपिंग पोर्टल देश में 15 लाख से अधिक स्कूलों की अवस्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है, जिसमें उनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं भी शामिल होती हैं. डेटा विश्लेषण पोर्टल स्कूलों की समग्र स्थिति के बारे में प्रतिशत जानकारी प्रदान करता है.

जानकारी साझा करने के लिए डिजिटल ढांचा (दीक्षा) 2.0

शिक्षकों को डिजिटल मंच उपलब्ध कराने के लिए दीक्षा पोर्टल 2017 में शुरू किया गया था. इससे उन्हें स्वयं सीखने और प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा शिक्षक समुदाय से जुडने का अवसर मिलता है. इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि शिक्षकों के लिए ई-विषयवस्तु की कवरेज और गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके. सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों तथा केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों से कहा गया है कि वे दीक्षा के लिए विषयवस्तु प्रदान करने में सक्रिय रूप से योगदान करें. एनसीईआरटी और सीबीएसई भी दीक्षा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सक्रिय रूप से योगदान कर रहे हैं. अभी तक 67,000 से अधिक विषयवस्तु आलेख दीक्षा पर डाले जा चुके हैं और 10.5 करोड़ से अधिक स्कैन इस्तेमाल किए गए हैं.

चार वर्षीय बी.एड समेकित पाठ्यक्रम

शिक्षक/शैक्षणिक कार्यक्रम में गुणात्मक सुधार लाने के लिए 29 मार्च 2019 को 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड पाठ्यक्रम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया.

कार्य निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक (पीजीआई)

राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में स्कूल शिक्षा प्रणाली के कार्य निष्पादन का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 70 सूचकांकों पर आधारित मैट्रिक्स डिजाइन किया है, जिसे कार्य निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक (पीजीआई) का नाम दिया गया है. इसके आधार पर राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को ग्रेड प्रदान किया जाता है.

ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड (ओडीबी)

इसका उद्देश्य मार्च 2023 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों में प्रत्येक के लिए 1,01,967 सरकारी और 42,917 सहायता प्राप्त स्कूलों और 1704 केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों यानी कुल मिला कर 1,46,588 स्कूलों में 2 स्मॉर्ट क्लास रूम उपलब्ध कराए जाएंगे. अनुषंगी वस्तुओं सहित हार्डवेयर की खरीद के लिए एक बारगी राशि के रूप में 2.40 लाख रुपये और विद्युत शुल्क, इंटरनेट कनेक्शन आदि व्यय के लिए आवर्ती लागत के रूप में 3.00 लाख रुपये (5 वर्ष के लिए) उपलब्ध कराए जाएंगे. अप्रैल 2020-21 से मार्च 2026-27 तक की अवधि के लिए कुल बजटीय आवश्यकता 8782.55 करोड़ रुपये (जिसमें 5671.50 करोड़ रुपये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा और 3111.05 करोड़ रुपये राज्यों द्वारा खर्च किए जाएंगे) की होगी. इस परियोजना की मुख्य विशेषताओं को अंतिम रूप दे दिया गया है और ईएफसी नोट का प्रारूप जल्दी ही (व्यय विभाग की सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपलोड किया जाएगा.

भाषा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वित्तीय सहायता कार्यक्रम (एएलटी)

पूर्वोत्तर राज्यों में हिंदी शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण तथा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 की शेष अवधि अर्थात् अक्तूबर 2019 से मार्च 2020 के लिए केंद्र प्रायोजित पुनर्गठित कार्यक्रम 'भाषा शिक्षकों की नियुक्ति (एएलटी) कार्यक्रम' शुरू किया गया. इस कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है.

मध्याह्न भोजन कार्यक्रम

स्कूलों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, जो मिड डे मील के रूप में लोकप्रिय है, पहले से जारी केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है, जो सरकारी, सरकार से सहायता प्राप्त, समग्र शिक्षा के तहत सहायता प्राप्त मदरसों और मक्तबों सहित विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूली बच्चों को कवर करता है. वर्ष 2018-19 के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत 11.34 लाख संस्थानों में अध्ययनरत 11.98 करोड़ बच्चों को शामिल किया गया. मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा कुल 24.95 लाख रसोइए एवं हेल्पर संलग्न किए गए, जिनमें 90 प्रतिशत से अधिक महिलाएं थीं. कुल 24.95 लाख रसोइयों में 21 प्रतिशत अजा, 15 प्रतिशत अजजा, 42 प्रतिशत अपिव और 7 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों से सम्बद्ध थे.

स्कूल पोषण उद्यान (एसएनजी)

सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को स्कूल पोषण उद्यानों संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. यह एक ऐसा स्थान है, जहां स्कूल परिसरों में जड़ी बूटियां, फल और सब्जियां उगाई जाती हैं ताकि उनका इस्तेमाल मध्याह्न भोजन तैयार करने में किया जा सके.

समग्र शिक्षा

पुस्तकालय अनुदान और पढ़ने को प्रोत्साहन

केंद्र सरकार ने स्कूली शिक्षा के लिए 2018-19 से समग्र शिक्षा नाम का एकीकृत कार्यक्रम प्रारंभ किया. समग्र शिक्षा के अंतर्गत पहली बार स्कूल स्तर पर पुस्तकालय अनुदान देने की शुरुआत की गई. राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे नेशनल बुक ट्रस्ट (एनबीटी) के एक स्कंध, राष्ट्रीय बाल साहित्य केंद्र (एनसीसीएल) की सहायता से चरणबद्ध तरीके से स्कूलों में रीडर्स क्लब स्थापित करें ताकि पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित किया जा सके. वर्ष 2019-20 में साक्षरता अनुदान के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के 10,09,357 स्कूलों के लिए 71164.78 लाख रुपये के व्यय का अनुमोदन किया गया.

खेल और शारीरिक शिक्षा

वर्ष 2019-20 के लिए विभिन्न श्रेणियों के 10,02,558 सरकारी स्कूलों के लिए खेल अनुदान के अंतर्गत 800.40 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमोदन किया गया. इस बीच, खेल और शारीरिक शिक्षा के नए दिशा निर्देश तैयार किए जा रहे हैं. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने एक से बारहवीं तक सभी कक्षाओं में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया है. बोर्ड स्कूलों को सलाह देता है कि वे स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत 3 क्षेत्रों अर्थात् स्वास्थ्य शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और योग को शामिल करें क्योंकि ये तीनों क्षेत्र समग्र स्वास्थ्य (भौतिक, मानसिक, बौद्धिक, भावात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक) का लक्ष्य हासिल करने के लिए अनिवार्य हैं.

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

समग्र शिक्षा के अंतर्गत 4 प्रकार के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं - प्रकार-1: के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के केजीबीवी विद्यालय; प्रकार 2: के अंतर्गत कक्षा 6 से 10; प्रकार 3 के अंतर्गत कक्षा 6 से 12 के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और प्रकार 4: के अंतर्गत कक्षा 11वीं से 12वीं के सभी मौजूदा बालिका छात्रावास शामिल हैं. समग्र शिक्षा के तहत देश में कुल 5930 केजीबी विद्यालय मंजूर किए गए हैं, जिनमें से 30 सितंबर, 2019 को 4881 केजीबीवी प्रचालित थे, जिनमें 6.18 लाख बालिकाओं को दाखिला दिया गया. वर्ष 2019-20 में देश में सभी केजीबीवी के लिए 424750.05 लाख

(शेष पृष्ठ 54 पर)

मानव संसाधन ...

(पृष्ठ 1 का शेष)

रुपये मंजूर किए गए.

स्कूली बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 18.10.2019 को सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को एक पत्र भेजा, जिसमें 'स्कूल सुरक्षा शपथ' बोर्ड पर प्रदर्शित करने अथवा सभी स्कूलों में प्रमुख स्थानों पर दीवार पर चित्रित करने का निर्देश दिया गया. समग्र शिक्षा के अंतर्गत इसके लिए प्रत्येक स्कूल के लिए 500 रुपये का प्रावधान किया गया. यह विभाग स्कूली बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए दिशा निर्देश तैयार कर रहा है. इस बारे में विद्यार्थियों, शिक्षकों, काउंसलरों, प्रधानाचार्यों और स्कूल प्रबंधन समितियों जैसे विभिन्न हितभागियों के साथ विचार विमर्श किया गया.

बालिकाओं के लिए आत्म रक्षा प्रशिक्षण

समग्र शिक्षा के अंतर्गत सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12वीं तक की बालिकाओं को आत्म रक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है. इस प्रयोजन के लिए हर महीने प्रत्येक विद्यालय हेतु प्रति माह 3000 रुपये की दर से तीन महीने के लिए धन प्रदान किया गया. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में भी आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है. समग्र शिक्षा के अंतर्गत वर्ष 2019-20 के लिए 180160 प्राथमिक विद्यालयों के वास्ते 15346.257 लाख रुपये और 81800 माध्यमिक स्कूलों के लिए 6656.358 लाख रुपये के खर्च का अनुमान लगाया गया.

समानता

स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर लिंग और सामाजिक अंतराल दूर करना समग्र शिक्षा कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है. इस कार्यक्रम का लक्ष्य सभी बालिकाओं और अजा, अजजा, अल्प संख्यक समुदायों और ट्रांसजेंडरों से संबंधित बच्चों तक पहुंचना है. राज्य विषयक हस्तक्षेपः समानता के अंतर्गत विशेष राज्य विषयक परियोजनाएं विविध उपायों के लिए चलाई जा रही हैं. इनके अंतर्गत स्कूली शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने, स्कूलों में विद्यार्थियों के बने रहने और शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है. इसके लिए दाखिला अभियान, शिक्षा बीच में न छोड़ने के महत्व पर बल देने के लिए प्रेरणा शिविरों के आयोजन, लिंग जागरूकता मॉड्यूल आदि कार्यक्रम चलाए जाते हैं. विविध उपायों के लिए राज्य विषयक परियोजनाएं परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा मंजूर की जाती हैं. इनकी मंजूरी सम्बद्ध राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा प्रस्तावित वार्षिक कार्य योजनाओं के आधार पर दी जाती है. वर्ष 2019-20 के लिए विभिन्न राज्य विषयक परियोजनाओं के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा स्तर पर कुल 21486.35 लाख रुपये और माध्यमिक स्तर पर 16083.22869 लाख रुपये मंजूर किए गए.

राष्ट्रीय साधन एवं योग्यता छात्रवृत्ति कार्यक्रम (एनएमएमएसएस)

इस कार्यक्रम के अंतर्गत 34493 विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप प्रदान करने के लिए 40.71 करोड़ रुपये मंजूर किए गए. इसके लिए एनएसपी पर लगभग 133460 सफल आवेदन प्राप्त हुए.

माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय बालिका प्रोत्साहन कार्यक्रम (एनएसआईजीएसई)

इसके अंतर्गत 28547 लाभार्थी बालिकाओं के लिए 8.56 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि मंजूर की गई है.

मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का कार्यक्रम (एसपीक्यूईएम)

मदरसों में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने के कार्यक्रम की परियोजना अनुमोदन बैठक 16 सितंबर 2019 को हुई, जिसमें सामान्य राज्यों और विधानसभा वाले संघ शासित प्रदेशों को 8788.00 लाख रुपये मंजूर किए गए. पूर्वोत्तर राज्यों और बिना विधानसभा वाले संघ शासित प्रदेशों के लिए क्रमशः 950.00 लाख रुपये और 2.00 लाख रुपये अनुमोदित किए गए. अभी तक एसपीक्यूईएम के अंतर्गत 5912.808 लाख रुपये राज्यों को जारी किए जा चुके हैं. 806.10 लाख रुपये की फाइल प्रोसेस की जा चुकी है/विचाराधीन है.

प्राइवेट सहायता प्राप्त/गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों का ढांचा विकास (आईडीएमआई)

आईडीएमआई की परियोजना अनुमोदन बैठक 27 नवंबर 2019 को हुई, जिसमें सामान्य राज्यों के लिए 2000.00 लाख रुपये और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 250 लाख रुपये मंजूर किए गए. आईडीएमआई कार्यक्रम के अंतर्गत 303.63 लाख रुपये की राशि जारी करने हेतु प्रोसेस की जा चुकी है.

विशेष जरूरत वाले बच्चों की कवरेज का संक्षिप्त विवरण-सीडब्ल्यूएसएन (2019-20)

- विशेष जरूरत वाले 20 लाख से अधिक बच्चे स्कूलों में दाखिल कराए गए हैं अथवा घर पर आधारित शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं.
- वर्ष 2019-20 में सीडब्ल्यूएसएन की शिक्षा के लिए समावेशी शिक्षा के विभिन्न उपायों के वास्ते 136375.31 लाख रुपये के व्यय का अनुमान लगाया गया.
- प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 8) पर 40,311 दृष्टिबाधित बच्चों को करीब 123.25 लाख रुपये की लागत से ब्रेल पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जा रही हैं.
- प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 8) पर अल्प दृष्टि वाले 91,254 बच्चों को मोटे 289.00 लाख रुपये की लागत से मोटे प्रिंट वाली पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं.
- 26817 विशेष शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए 619.09 लाख रुपये के परिव्यय का अनुमान लगाया गया.
- जरूरत वाली 5.96 लाख बालिकाएं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से विशेष वजीफा प्राप्त कर रही हैं.
- एडीआईपी जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से 2.32 लाख से अधिक सीडब्ल्यूएसएन बच्चे सहायता और उपकरण इस्तेमाल कर रहे हैं.
- सामाजिक समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए 17734 खेल आयोजनों और भ्रमण यात्राओं के लिए 1911.05 लाख रुपये के कुल परिव्यय का अनुमान लगाया गया.
- प्राथमिक स्तर पर करीब 64.24 प्रतिशत और माध्यमिक स्तर पर 58.28 प्रतिशत स्कूलों में हैंडरेल्स के साथ रैम्प प्रदान किए गए हैं. इसी प्रकार प्राथमिक स्तर पर करीब 19.59 प्रतिशत स्कूलों में और माध्यमिक स्तर पर 24.40 प्रतिशत स्कूलों में दिव्यांगजन अनुकूल शौचालयों का निर्माण किया गया है ताकि नियमित स्कूलों में सीडब्ल्यूएसएन की धारण क्षमता बढ़ाई जा सके.
- 58392 सहायक यंत्रों, उपकरणों और शिक्षण शिक्षार्थी सामग्री (टीएलएम) के लिए 1995.93 लाख रुपये का परिव्यय मंजूर किया गया.
- प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक सीडब्ल्यूएसएन बच्चों की विविध और विशिष्ट जरूरतें पूरी करने के लिए 28285 विशेषज्ञों और विशेष शिक्षकों की नियुक्ति का अनुमान लगाया गया है.

सीडब्ल्यूएसएन के लिए स्वायत्त संगठनों के प्रयास

- सीडब्ल्यूएसएन के लिए ई-पाठशाला पोर्टल पर पहुंच योग्य फार्मेट में पुस्तकें एनसीईआरटी द्वारा विकसित की गई हैं. दृष्टिबाधित बच्चों की सहायता के लिए ई-पाठशाला मोबाइल ऐप टैक्स्ट टू स्पीच की सुविधा प्रदान करता है.
- एनसीईआरटी द्वारा श्रव्य पुस्तकें विकसित की गई हैं, जिनमें पाठ्य पुस्तकों को श्रव्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है ताकि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की सहायता की जा सके.
- एनसीईआरटी ने 25 मानचित्रों और रेखा चित्रों के साथ ब्रेल और अंग्रेजी टैक्स्ट में टेक्टाइल मैप बुक विकसित की है ताकि सहयोगात्मक सीखने को प्रोत्साहित किया जा सके.
- सीडब्ल्यूएसएन के लिए सीबीएसई के प्रावधानः कक्षा 10 और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए स्क्राइब की सुविधा और क्षतिपूर्ति समय के बारे में लागू छूट/रियायतें संबंधी नियमः विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 में परिभाषित विकलांगताओं से सम्बद्ध उम्मीदवारों को एक स्क्राइब के इस्तेमाल की अनुमति अथवा क्षतिपूर्ति समय आदि की सुविधा प्रदान की गई है.

जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) भवनों का निर्माण

मंत्रालय की 100 दिन की कार्य योजना के अनुसार 10 जवाहर नवोदय विद्यालयों अर्थात् कांशीराम नगर (यूपी), मलकानगिरि-2 (ओडिशा), सीतापुर-2 (उ.प्र), डांग (गुजरात), नवसारी (गुजरात), पुरी (ओडिशा), पलवल (हरियाणा), भंडारा (महाराष्ट्र), झाबुआ-2 (एमपी), अहमदाबाद (गुजरात) के नवनिर्मित भवनों का उद्घाटन किया गया. 100 दिन की कार्य योजना के हिस्से के रूप में 10 जवाहर नवोदय विद्यालयों के संदर्भ में आधारशिला रखी गई और निर्माण कार्य शुरू किया गया. ये हैं - सेफइजाला (त्रिपुरा), दक्षिण त्रिपुरा (त्रिपुरा), दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स (मेघालय), जलपाईगुड़ी (पश्चिम बंगाल), कलबुर्गी-1 (कर्नाटक) और कोलार (कर्नाटक), झाबुआ (मध्य प्रदेश) और महीसागर (गुजरात). जेएनवी श्रीकाकुलम, जेएनवी विशाखापट्टनम, जेएनवी विजयनगरम, जेएनवी कोडागू और जेएनवी मांड्या में अतिरिक्त छात्रावासों का निर्माण पूरा किया गया है. 176 स्थानों पर रूफ टॉप ग्रिड कनेक्टिड सोलर पावर के कार्यान्वयन के लिए ढांचा निर्माण कार्य पूरा किया गया. 12 शहरों में बिजली का उत्पादन प्रारंभ भी हो गया. अन्य जेएनवी में नेट मीटरिंग की प्रतीक्षा की जा रही है.

भर्ती

सभी जवाहर नवोदय विद्यालयों में एक पुरुष और एक महिला काउंसलर की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो गई है. 9 जुलाई 2019 को 2370 पद भरने के लिए विज्ञापित किए गए थे, जिनसे संबंधित प्रक्रिया पूर्ण होने के अंतिम चरण में है. 218 पीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति प्रस्ताव जारी किए गए हैं. उनके कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति की प्रतीक्षा है.

शाला दर्पण

एनवीएस के शाला दर्पण पोर्टल का शुभारंभ मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय प्रेक्षागृह में 6 नवंबर 2019 को किया. इससे संगठन में अपनाई जा रही सेवा प्रक्रियाओं की हस्तचालित प्रणाली समाप्त हो जाएगी और निर्णय करने में सहायक वास्तविक समय डेटा तक पहुंच में सुधार आएगा तथा स्कूल संचालन में सक्षमता और पारदर्शिता बढ़ेगी. शाला दर्पण परियोजना का विकास इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी का विकास सी-डेक की मदद से किया जा रहा है.

नवोदय विद्यालय विद्यार्थियों की शैक्षिक उत्कृष्टता

एनवीएस विद्यार्थियों का आईआईटीज़, एनआईटीज़ और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेशः 2019

जेईई		एनईईटी	
जेईई मुख्य परीक्षा में बैठे	11733	नीट में बैठे	16156
जेईई मुख्य परीक्षा क्वालिफाई की	4451	नीट क्वालिफाई की	12654
जेईई अडवांस्ड परीक्षा की प्रथम सूची में क्वालिफाई	966		

डिजिटल उपाय

कक्षा 6 में प्रवेश के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है, जिससे ग्रामीण आबादी की आवेदन प्रक्रिया तक बेहतर पहुंच कायम करने में मदद मिली है. फेसलेस प्रवेश प्रक्रिया के फलस्वरूप पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार समाप्त करने में मदद मिली है. स्थानांतरण की प्रक्रिया ऑनलाइन बनाई गई है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और प्रक्रिया समय पर पूरी होने में मदद मिली है. भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है और नियुक्ति तक फेसलेस रहती है. उम्मीदवार अपने लॉगइन पासवर्ड का इस्तेमाल करके नियुक्ति पत्र भी डाउनलोड कर रहे हैं.

केंद्रीय विद्यालय संगठन की उपलब्धियां

- **नवनिर्मित स्कूल भवनों का उद्घाटनः** 17 नए केंद्रीय विद्यालय भवनों का निर्माण और उद्घाटन किया गया.
- **स्कूल भवनों की आधार शिला रखनाः** मानव संसाधन विकास मंत्री ने केंद्रीय विद्यालयों के 7 स्कूल भवनों की आधारशिला रखी.
- **नए केंद्रीय विद्यालय खोलनाः** पिछले 6 महीनों में 25 केंद्रीय विद्यालय खोले गए हैं.
- **रिक्तियों को भरना :** विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों/केवीएस (मुख्यालय) में पिछले 6 महीनों में स्टाफ की तैनाती का ब्यौरा नीचे दिया गया हैः

क्रसं	पद का नाम	पे लेवल	जारी किए गए नियुक्ति प्रस्तावों की संख्या
1.	प्राथमिक शिक्षक	06	3000
2.	टीजीटी (अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, संस्कृत)	07	3473
3.	सहायक अनुभाग अधिकारी	06	31
4.	वरिष्ठ सचिवालय सहायक	04	218
5.	कनिष्ठ सचिवालय सहायक	02	684
6.	आशुलिपिक ग्रेड-2	04	37
	कुल		**7443**

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की उपलब्धियां - 2019

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष के दौरान कई उपलब्धियां हासिल कीं और नए उपाय शुरू किए जिनमें अन्य के अलावा शिक्षण कार्यक्रम केंद्रों की स्थापना, स्कूल शिक्षकों का प्रशिक्षण, शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया, नया विद्या दान कार्यक्रम, विद्यार्थियों को पीआईएसए 2021 के लिए तैयार करना, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाना, आर्यभट्ट गणित प्रतियोगिता का आयोजन, स्कूली बच्चों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पुस्तकें प्रदान करना और फिट इंडिया, स्वच्छता, ईबीएसबी जैसे राष्ट्रीय स्तर के अभियानों में भागीदारी शामिल है.

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी)

एनसीटीई ने 4 वर्षीय एकीकृत अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी)के लिए मान्यता प्रदान करने हेतु संस्थानों से आवेदन आमंत्रित किए. संस्थानों ने ऑनलाइन आवेदन जमा कराए, जिन्हें सम्बद्ध विनियमों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रोसेस किया जाएगा. आवेदन 03.06.2019 और 31.07.2019 के बीच आमंत्रित किए गए थे.

ऑनलाइन कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रणाली (पीएआर) का शुभारंभ

एनसीटीई द्वारा मान्यता प्रदान करने की शर्तों में से एक यह है कि कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट वार्षिक आधार पर सीधे फाइल करनी होती है, जिसमें सनदी लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा विवरण भी शामिल होता है. ऑनलाइन कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रणाली का औपचारिक शुभारंभ 23 सितंबर 2019 को किया गया तथा सभी मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए नियामक मानदंडों के बारे में डेटा भरना अनिवार्य बनाया गया.

ऑनलाइन अध्यापक-विद्यार्थी पंजीकरण प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ (ओटीपीआरएमएस)

कुछ संभावित नियोक्ता किसी व्यक्ति को शिक्षक के रूप में नियोजित करने से पहले डिग्री/डिप्लोमा/अध्यापक शिक्षा में प्रमाणपत्र के बारे में एनसीटीई से मान्यता संबंधी स्थिति की जांच कराते हैं. इस बारे में एनसीटीई ने ऑनलाइन अध्यापक-विद्यार्थी पंजीकरण प्रबंधन प्रणाली शुरू की है ताकि एनसीटीई मान्यताप्राप्त संस्थानों से शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को सुविधा प्रदान की जा सके. इस कार्यक्रम का शुभारंभ 26 जुलाई 2019 को किया गया.

रजत जयंती समारोह

एनसीटीई ने अपने स्वर्ण जयंती वर्ष में 2 दिन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 17 और 18 अगस्त 2019 को आयोजित किया, जिसका विषय था - ''अध्यापक शिक्षा की यात्राः स्थानीय से वैश्विक''. सम्मेलन में भारतीय शिक्षा प्रणाली की उपलब्धियों को उजागर किया गया और शिक्षक शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण वैश्विक पद्धतियों को शामिल करने में सहायता मिली.

एनसीटीई ''परियोजना लाइटहाउस'' शुरू करने की दिशा में अपने संसाधन लगाना चाहती है. पहले चरण में 700 संस्थानों का चयन करने का प्रयास है, जिसमें देश के प्रत्येक जिले में लगभग एक स्थान शामिल किया जाएगा. भागीदार शिक्षक शिक्षा संस्थानों का चयन एनसीटीई द्वारा एक पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा और इन संस्थानों की शैक्षिक और प्रशासनिक रूप में मदद की जाएगी और उन्हें 2020-21 के सत्र से 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम संचालित करने का अवसर दिया जाएगा. इस कार्यक्रम से वर्ष 2020-22 की अवधि में 70,000 अनुकरणीय शिक्षक तैयार होने की संभावना है. 700 अध्यापक शिक्षा संस्थानों का चयन लगातार 5 वर्ष तक किया जाएगा, जिसके बाद 3500 मॉडल अध्यापक शिक्षा संस्थान क्षमतावान बनाए जा सकेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय क्षमता के कुल 3,50,000 गुणवत्तापूर्ण शिक्षक तैयार करेंगे. इस तरह चुने गए अध्यापक शिक्षा संस्थानों को कई विशिष्ट उपायों से सहायता प्रदान की जाएगी, जैसे विद्यार्थियों के दाखिले के लिए केंद्रीकृत प्रवेश परीक्षा, एक संशोधित और अद्यतन पाठ्यक्रम शिक्षकों का क्षमता निर्माण आदि. इन अध्यापक शिक्षा संस्थानों के कुछ चुने हुए विद्यार्थी/शिक्षकों को अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां दिलाने का भी लक्ष्य रखा गया है.

हर वर्ष बीस अनुकरणीय अध्यापक- शिक्षकों के लिए ''सर्वश्रेष्ठ अध्यापक शिक्षक पुरस्कार'' प्रारंभ

एनसीटीई ने हर वर्ष 20 प्रतिभाशाली अध्यापक शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान करने का एक कार्यक्रम शुरू किया है. प्रथम पुरस्कार 2020 में दिया जाएगा.

-पसूका